दैनिक
न्याय साक्षी
अधिकार से न्याय तक

आवश्यक सूचना

आप सभी को सूचित करते हर्ष हो रहा है, कि न्यायसाक्षी अधिकार से न्याय तक का सर्वे का कार्य तेजी से चल रहा है, जल्द ही सर्वे की टीम आपके घर विजिट करेगी, कृपया अपनी प्रति सुरक्षित कराएं।

RNI NO - CHHHIN/2018/76480 ‖ Postal Registration No-055/Raigarh DN CG ‖ रायगढ़, शनिवार 03 जुलाई 2021 ‖ पृष्ठ-4, मूल्य 3 रूपए ‖ वर्ष-03, अंक- 273

महत्वपूर्ण एवं खास

12 राज्यों में डेल्टा ए प्लस वेरिएंट संक्रमण के 56 मामले

नई दिल्ली (आरएनएस)। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की शुक्रवार को हुई प्रेसवार्ता में नीति आयोग के सदस्य (स्वास्थ्य) डॉ. वीके पॉल भी मौजूद रहे। एक सवाल के जवाब में उन्होंने बताया कि फिलहाल देश के 12 राज्यों में कोरोना वायरस के डेल्टा ए प्लस (डेल्टा एवाई.1) से संक्रमण के 56 मामले हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि हम जॉनसन एंड जॉनसन की एक खुराक वाली वैक्सीन को लेकर भी उनसे बातचीत कर रहे हैं। उनकी वैक्सीन का उत्पादन बाहर हो रहा है। योजना के अनुसार, इस वैक्सीन का उत्पादन भी हैदराबाद स्थित बायोलॉजिकल ई में किया जाएगा। उल्लेखनीय है कि भारत में शुक्रवार को एक दिन में कोविड-19 के 46,617 नए मामले सामने आने के बाद देश में संक्रमितों की संख्या बढ़कर तीन करोड़ चार लाख 58 हजार 251 हो गई। वहीं, मरीजों के ठीक होने की राष्ट्रीय दर (रिकवरी रेट) 97 फीसदी के पार चली गई है। इसके अलावा केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से शुक्रवार को जारी आंकड़ों के अनुसार देश में कोरोना वायरस संक्रमण से पीड़ित 853 और लोगों की मौत के बाद, इस वैश्विक महामारी की वजह से जान गंवाने वालों का आंकड़ा बढ़कर अब चार लाख 312 पर पहुंच गया है।

वाको इंडिया किकबॉक्सिंग फेडरेशन को एनएसएफ के रूप में सरकारी मान्यता मिली

नईदिल्ली (आरएनएस)। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय ने भारत में किकबॉक्सिंग खेल के प्रचार और विकास के लिए वाको इंडिया किकबॉक्सिंग फेडरेशन को राष्ट्रीय खेल महासंघ (एनएसएफ) के रूप में मान्यता प्रदान करने का निर्णय लिया है। वाको इंडिया किकबॉक्सिंग फेडरेशन वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ किकबॉक्सिंग ऑर्गनाइजेशन्स (वाको) से संबद्ध है, जो कि किकबॉक्सिंग के खेल के लिए अंतर्राष्ट्रीय फेडरेशन है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति (आईओसी) के कार्यकारी बोर्ड ने 10 जून को अपनी बैठक में वाको को खेल के ओलंपिक परिवार का पूर्ण रूप से मान्यता प्राप्त सदस्य बनने की सिफारिश को स्वीकृति दे दी है। वाको 30 नवंबर 2018 से आईओसी का अस्थायी रूप से मान्यता प्राप्त सदस्य है। वाको की पूर्ण मान्यता अंतिम रूप से जुलाई 2021 में टोक्यो में आईओसी सत्र के दौरान तय की जाएगी। ओलंपिक आंदोलन में पूरी तरह से शामिल और स्वीकार किया जाना किकबॉक्सिंग के खेल की मान्यता और विकास के लिए महत्वपूर्ण है। यह उम्मीद की जाती है कि वाको इंडिया किकबॉक्सिंग फेडरेशन को एनएसएफ के रूप में सरकार की मान्यता के साथ, किकबॉक्सिंग का खेल देश में तेज गति से विकसित होगा।

राज्य और केन्द्रशासित प्रदेशों को 33 करोड़ 63 लाख से अधिक टीके उपलब्ध कराए गये

नईदिल्ली (आरएनएस)। केंद्र सरकार पूरे देश में कोविड-19 टीकाकरण की रफ्तार तेज करने और दायरा बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। कोविड-19 टीके की व्यापक उपलब्धता से जुड़ा नया चरण 21 जून, 2021 से शुरू हुआ। टीकाकरण अभियान ज्यादा टीकों की उपलब्धता के साथ, राज्यों एवं केंद्रशासित राज्यों को टीकाकरण उपलब्धता की अग्रिम जानकारी देकर तेज किया गया है ताकि टीकों को लेकर राज्य और केंद्रशासित प्रदेश बेहतर योजना बना सकें और टीकों की आपूर्ति श्रृंखला सुव्यवस्थित की जा सके। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत भारत सरकार राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को निःशुल्क कोविड टीके उपलब्ध कराकर उनकी मदद कर रही है। सबको टीका उपलब्ध कराने से जुड़े कोविड-19 टीकाकरण अभियान के नये चरण के तहत केंद्र सरकार देश में टीका विनिर्माताओं द्वारा उत्पादित 75 प्रतिशत टीके खरीदेगी और उनकी राज्यों एवं केंद्रशासित प्रदेशों को (निःशुल्क) आपूर्ति करेगी। भारत सरकार ने अब तक राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों को कोविड टीके की 33.63करोड़ से अधिक खुराक (33,63,78,220) मुफ्त श्रेणी और राज्यों द्वारा सीधी खरीद की श्रेणी के माध्यम से प्रदान की हैं। इसके अलावा टीके की 44,90,000 खुराक प्रक्रियारत हैं और अगले तीन दिनों में राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों को प्रदान कर दी जाएंगी।

केन्द्र ने छह राज्यों में कोविड के बढ़ते मामलों के मद्देनजर विशेषज्ञ दल भेजे

नईदिल्ली (आरएनएस)। केंद्र सरकार समग्र सरकार और समग्र समाज केदृष्टिकोण के साथ वैश्विक महामारी कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई का नेतृत्व कर रही है। कोविड प्रबंधन के लिए विभिन्न राज्य/केंद्र शासित प्रदेशों की सरकारों की कोशिशों को मजबूत करने के लिए जारी प्रयास के रूप में, केंद्र सरकार समय-समय पर विभिन्न राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों का दौरा करने के लिए केंद्रीय टीमों की प्रतिनियुक्ति करती रही है। ये टीमें राज्य/केंद्र शासित प्रदेशों के अधिकारियों के साथ बातचीत करती हैं और उनके सामने आने वाली चुनौतियों एवं मुद्दों की प्रत्यक्ष समझ प्राप्त करती हैं ताकि राज्यों की ओर से जारी गतिविधियों को मजबूत किया जा सके तथा किसी तरह की बाधाएं होने पर उन्हें दूर किया जा सके।

केंद्र ने केरल, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, ओडिशा, छत्तीसगढ़ और मणिपुर में कोविड-19 मामलों की बढ़ती संख्या को देखते हुए बहु-अनुशासनात्मक टीमों की प्रतिनियुक्ति की है। ईएमआर के अतिरिक्त उपमहानिदेशक और निदेशक डॉ. एल स्वस्तिचरण मणिपुर जाने वाली टीम का नेतृत्व करेंगे। अरुणाचल प्रदेश की टीम का नेतृत्व अखिल भारतीय स्वच्छता और जन स्वास्थ्य संस्थान (एआईआईएच एंड पीएच) के प्रोफेसर, डॉ. संजय साधुखान करेंगे।त्रिपुरा जाने वाली टीम का नेतृत्वअखिल भारतीय स्वच्छता और जन स्वास्थ्य संस्थान (एआईआईएच एंड पीएच) के प्रोफेसर डॉ. आर एन सिन्हा करेंगे। केरल जाने वाली टीम का नेतृत्व क्षेत्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण कार्यालय (आरओएचएफडब्ल्यू), ग्रुप 2 जन स्वास्थ्य विशेषज्ञ डॉ. रुचि जैन करेंगी। ओडिशा जाने वाली टीम का नेतृत्व अखिल भारतीय स्वच्छता और जन स्वास्थ्य संस्थान (एआईआईएच एंड पीएच) के जन स्वास्थ्य विशेषज्ञ डॉ. ए डैनकरेंगे और छत्तीसगढ़ जाने वाली टीम का नेतृत्व एम्स रायपुर के सहायक प्रोफेसर डॉ. दिबाकर साहू करेंगे। लक्षित कोविड प्रतिक्रिया और प्रबंधन के लिए तथा महामारी से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए टीमें उनके प्रयासों में सहयोग करेंगी। इन राज्यों के लिए गठित दो सदस्यीय उच्च स्तरीय टीम में एक चिकित्सक और एक सार्वजनिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ शामिल हैं। टीमें तुरंत राज्यों का दौरा करेंगी और कोविड-19 प्रबंधन के समग्र कार्यान्वयन की निगरानी करेंगी, विशेष रूप से जांच पर ध्यान देंगी। इनमें निगरानी एवं नियंत्रण संचालन; कोविड उपयुक्त व्यवहार तथा उसका प्रवर्तन; अस्पताल के बिस्तरों की उपलब्धता; एम्बुलेंस, वेंटिलेटर, चिकित्सीय ऑक्सीजन आदि सहित पर्याप्त रसद, और कोविड-19 टीकाकरण की प्रगति शामिल हैं। टीमें स्थिति की निगरानी करेंगी और उपचारात्मक कार्रवाई का सुझाव भी देंगी।

केंद्रीय टीमें स्थिति का आकलन करेंगी और संबंधित राज्य सरकारों को सार्वजनिक स्वास्थ्य गतिविधियों पर उपचारात्मक कार्रवाई का सुझाव देंगी। रिपोर्ट की प्रति केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय को भी उपलब्ध कराई जाएगी।

अब ड्रोन का इस्तेमाल नहीं होगा आसान

» जम्मू हमले के बाद नए नियम बना रही सरकार

नई दिल्ली (आरएनएस)। बीते 27 जून को जम्मू में वायु सेना स्टेशन पर हुए ड्रोन हमले के बाद, नागरिक उड्डयन मंत्रालय भारत में ड्रोन के उपयोग को नियंत्रित करने के लिए नए नियम तैयार करने की प्रक्रिया में है। सार्वजनिक परामर्श के लिए नियमों का नया सेट 15 अगस्त के आसपास प्रकाशित होने की उम्मीद है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक, ये नियम मौजूदा मानव रहित विमान प्रणाली नियमों को अपडेट कर तैयार किया जा रहा है, जिन्हें इस साल की शुरुआत में ड्रोन के उपयोग को रेगुटेल करने के लिए जारी किया गया था।

एक रिपोर्ट के अनुसार, नए नियमों से मेड इन इंडिया एंटी-ड्रोन समाधानों का पता लगाने की उम्मीद है। ये 27 जून को जम्मू में विस्फोटों को अंजाम देने वाले और बाद में क्षेत्र में देखे गए ड्रोन का पता लगाएंगे और प्रभावी ढंग से उन्हें बेअसर कर देंगे। ये संशोधित नियम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने पेश किए गए थे, जब उन्होंने 29 जून को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह और नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप पुरी से अपने आवास पर मुलाकात की थी और जम्मू में स्थिति और सामान्य सुरक्षा तैयारियों का जायजा लिया था।

सूत्रों के मुताबिक नए नियम कमोबेश तैयार हैं लेकिन अभी कुछ काम होना बाकी है। नए नियमों के प्रकाशन की अनुमानित समय सीमा 15 अगस्त है। 27 जून को, जम्मू वायु सेना स्टेशन पर दो आईईडी बम गिराने के लिए कम-उड़ान वाले ड्रोन का इस्तेमाल किया गया था। यह संभवतः देश में किसी रक्षा प्रतिष्ठान पर पहला ड्रोन हमला था। विस्फोटों ने रात में स्टेशन के उच्च सुरक्षा तकनीकी क्षेत्र को हिलाकर रख दिया। आपको बता दें कि इस हमले में भारतीय वायु सेना के दो कर्मियों को मामूली चोटें आईं।

अगर मंत्री सही नहीं तो पीएम ही लेंगे एक्शनः सुको

नई दिल्ली (आरएनएस)। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को केन्द्रीय मंत्री वीके सिंह के खिलाफ दायर उस याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई करने से इनकार कर दिया, जिसमें दावा किया गया था कि चीन के साथ वास्तविक नियंत्रण रेखा (एलएसी) पर भारत की आधिकारिक स्थिति पर टिप्पणी कर उन्होंने अपनी शपथ का उल्लंघन किया है। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर मंत्री सही नहीं है, तो प्रधानमंत्री इस संबंध में कार्रवाई करेंगे, अदालत कुछ नहीं कर सकती। प्रधान न्यायाधीश एनवी रमण, न्यायमूर्ति एएस बोपन्ना और न्यायमूर्ति ऋषिकेश रॉय की एक पीठ ने इस टिप्पणी के साथ ही तमिलनाडु के निवासी याचिकाकर्ता चंद्रशेखरन रामासामी की याचिका खारिज कर दी। रामासामी खुद को एक वैज्ञानिक बताते हैं। सुप्रीम कोर्ट की इस पीठ ने कहा कि अगर आपको किसी मंत्री का बयान पसंद नहीं आया, तो इसका मतलब यह नहीं है कि आप याचिका दायर कर उसे बयान वापस लेने के लिए कहेंगे। अगर मंत्री सहीं नहीं है, तो प्रधानमंत्री इस संबंध में कार्रवाई करेंगे, अदालत कुछ नहीं कर सकती। पीठ ने याचिकाकर्ता से कहा कि ऐसा प्रतीत होता है कि आप वैज्ञानिक हैं, इसलिए आपको अपनी क्षमता का उपयोग देश के लिए कुछ करने के लिए करना चाहिए। हम याचिका खारिज कर रहे हैं। याचिका में केन्द्र को यह निर्देश देने का अनुरोध किया गया था कि वह यह घोषणा करे कि केन्द्रीय मंत्री जनरल (सेवानिवृत्त) वीके सिंह ने चीन के साथ वास्तविक नियंत्रण रेखा पर भारत की स्थिति के संबंध में कथित टिप्पणी कर अपनी शपथ का उल्लंघन किया है।

जून में भारतीय रेल ने लदान और आय अर्जन के संबंध में तेजी बनाये रखी

» रेल मंत्रालय ने कहा

नईदिल्ली (आरएनएस)। कोविड चुनौतियों के बावजूदभारतीय रेलवे ने जून 2021 में आय और माल ढुलाई के रूप में उच्चगति को बरकरार रखा है। मिशन मोड में जून 2021 मेंभारतीय रेलवे ने 112.65 मिलियन टन माल की ढुलाई की, जो जून 2019 (101.31 मिलियन टन) की तुलना में 11.19 प्रतिशत अधिक है। यह एक सामान्य वर्ष था। इसी अवधि के लिए यानिजून 2020 (93.59 मिलियन टन) की तुलना में यह ढुलाई 20.37 प्रतिशत अधिक रही है।

जून 2021 के दौरान ढुलाई की गई महत्वपूर्ण वस्तुओं में 50.03 मिलियन टन कोयला, 14.53 मिलियन टन लौह-अयस्क, 5.53 मिलियन टन कच्चा लोहा और तैयार स्टील, 5.53 मिलियन टन खाद्यान्न, 4.71 मिलियन टन उर्वरक, 3.66 मिलियन टन खनिज तेल शामिल है। 6.59 मिलियन टन सीमेंट (क्लिंकर को छोड़कर) और 4.28 मिलियन टन क्लिंकर शामिल है।

जून 2021 के महीने में, भारतीय रेलवे ने माल ढुलाई से 11,186.81 करोड़ रुपये की आय अर्जित की, जो जून 2020 की तुलना में 26.7 प्रतिशत अधिक (8,829.68 करोड़ रुपये) और जून 2019 की तुलना में 4.48 प्रतिशत अधिक (10,707.53 करोड़ रुपये) है।

गौरतलब है कि रेलवे माल ढुलाई को आकर्षक बनाने के लिए भारतीय रेलवे में कई तरह की रियायतें/छूट भी दी जा रही हैं।

यह उल्लेखनीय है कि मौजूदा नेटवर्क में मालगाड़ियों की गति बढ़ा दी गई है।

माल ढुलाई की गति में सुधार से सभी हितधारकों के लिए लागत की बचत होती है। पिछले 19 महीनों में माल ढुलाई की गति दोगुनी हो गई है।

भारतीय रेलवे द्वारा कोविड-19 का उपयोग चौतरफा दक्षता और प्रदर्शन में सुधार के अवसर के रूप में किया गया है।

टीकाकरण अभियान राष्ट्रीय आंदोलन बनना चाहिएः नायडू

नईदिल्ली (आरएनएस)। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने टीकों और दवाओं को खोजने के काम में गति लाने के लिए नए कोविड-19 वेरिएंट के जीनोम अनुक्रमण को तेज करने का आह्वान किया है।

उपराष्ट्रपति हैदराबाद पहुंचने के तुरंत बाद सीसीएमबी के लाकोन्स (लुप्तप्राय प्रजातियों के संरक्षण के लिए प्रयोगशाला) सुविधा को देखने गए। उन्होंने लाकोन्स के प्रभारी वैज्ञानिक डॉ. कार्तिकेयन वासुदेवन के प्रेजेंटेशन को देखा और सुविधा में राष्ट्रीय वन्यजीव आनुवंशिक संसाधन बैंक, सहायक प्रजनन प्रयोगशाला और पशु पिंजरों को देखा।

नायडू ने वैज्ञानिकों और रिसर्च स्कॉलरों को संबोधित करते हुए कहा कि एक सहायक संयोजक के रूप में अनुक्रमणनए वायरल म्यूटेशनों के उद्भव की पहचान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और इस प्रकार कोविड-19 के प्रसार का मुकाबला करने में मदद करता है। उन्होंने कहा कि इससे समय पर हस्तक्षेप करने में भी मदद मिलेगी।

देश के कुछ चिड़ियाघरों में बिलाव के कोविड-19 की चपेट में आने की रिपोर्ट के आलोक में नए वैरिएंट के जीनोम अनुक्रमण की आवश्यकता को महत्वपूर्ण बताते हुए नायडू ने कहा कि एक वायरस की प्रजातियों में उछाल यानी मनुष्यों से जानवरों या जानवरों से मनुष्यों में उछाल से नए वैरिएंट पैदा हो सकते हैं और महामारी के खिलाफ चल रही लड़ाई में नई चुनौतियां खड़ी हो सकती हैं।

उपराष्ट्रपति ने एक सार्वभौमिक टीका विकसित करने की व्यवहार्यता का अध्ययन करने के लिए अनुसंधान संस्थानों द्वारा अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को मजबूत बनाने की आवश्यकता पर भी बल दिया जो विभिन्न सार्स-सीओवी-2 वेरिएंट को प्रभावहीन कर सकता है।

लोगों से टीका लगवाने में हिचकिचाहट दूर करने की अपील करते हुए नायडू ने दोहराया कि भारत में बने टीके सुरक्षित और प्रभावी हैं और सभी को टीका लगवाना चाहिए और दूसरों को भी ऐसा करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। उन्होंने सांस्कृतिक और खेल क्षेत्र के प्रसिद्ध लोगों से टीकाकरण अभियान में सक्रिय भागीदार बनने और लोगों को टीकाकरण के लिए प्रेरित करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि टीकाकरण अभियान राष्ट्रीय आंदोलन बनना चाहिए।

नायडू ने कोविड-19 को कम करने में सीसीएमबी के योगदान की सराहना करते हुए कहा कि संस्थानों के बीच सहयोग की मजबूत व्यवस्था होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि लाकोन्स-सीसीएमबी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों स्तरों पर संपर्क बनाने, संक्रामक रोगों के उद्भव को समझने और भविष्य में ऐसी महामारी को रोकने के लिए सही स्थिति में थे।

राज्यों को नहीं मिला सामाजिक-शैक्षणिक पिछड़ा वर्ग घोषित करने का अधिकार

नई दिल्ली (आरएनएस)। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार की उस याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें 5 मई को 102वें संविधान संशोधन से जुड़े फैसले पर पुनर्विचार करने की मांग की गई थी। शीर्ष अदालत ने उस फैसले में कहा था कि राज्यों के पास सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग की पहचान करने का अधिकार नहीं है।

जस्टिस अशोक भूषण, जस्टिस एल नागेश्वर राव, जस्टिस एस अब्दुल नजीर, जस्टिस हेमंत गुप्ता और जस्टिस एस रविंदर भट की पीठ ने कहा कि केंद्र ने पुनर्विचार याचिका में जो आधार दिए हैं, उन पर पहले ही गौर किया जा चुका है। ऐसे में 5 मई के आदेश में दखल देने का कोई आधार नहीं बनता। पीठ ने पुनर्विचार याचिका पर ओपन कोर्ट में सुनवाई की केंद्र की मांग भी ठुकरा दी। पीठ ने 28 जून को अपने चैंबरों में इस याचिका पर विचार किया था। दरअसल 5 मई को सुप्रीम कोर्ट की पांच सदस्यीय संविधान पीठ ने बहुमत (3-2) के फैसले में कहा था कि 102वें संशोधन के बाद राज्यों के पास सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों की पहचान करने का अधिकार खत्म हो गया है। किसी समुदाय को पिछड़ा वर्ग सूची में डालना या निकालना, राष्ट्रपति का अधिकार है।

देश में अब तक कोरोना ने ली चार लाख से ज्यादा की जान, 24 घंटे में 46,617 नए मामले, 853 मरीजों की मौत

नई दिल्ली (आरएनएस)। देश में कोरोना वायरस के दैनिक मामलों में लगातार उचार-चढ़ाव जारी है। पिछले 24 घंटे में देश में कोरोना वायरस के 46,617 नए मामले सामने आए और इसी दौरान 853 मरीजों ने इस खतरनाक वायरस के आगे दम तोड़ा है। यह राहत की बात है कि देश में कोरोना को मात देकर स्वस्थ्य होने वालों की संख्या तेजी के साथ बढ़ रही है और वहीं सक्रीय मरीजों की संख्या में तेजी से गिरावट दर्ज की जा रही है। वहीं अब तक कोरोना चार लाख लोगों को अपन काल का ग्रास बना चुका है।

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक एक दिन कोविड-19 के 46,617 नए मामले सामने आने के बाद देश में संक्रमितों की संख्या बढ़कर 3,04,58,251 हो गई। वहीं मरीजों के ठीक होने की राष्ट्रीय दर 97 प्रतिशत के पार चली गई है। वहीं देश में संक्रमण से 853 और लोगों की मौत के बाद, इस महामारी की वजह से जान गंवाने वालों की संख्या बढ़कर 4,00,312 हो गई है। देश में उपचाराधीन मरीजों की संख्या भी कम होकर 5,09,637 हो गई है, जो कुल मामलों का 1.67 प्रतिशत है। मरीजों के ठीक होने की राष्ट्रीय दर बढ़कर 97.01 प्रतिशत हो गई है। पिछले 24 घंटे में उपचाराधीन मामलों में कुल 13,620 की कमी आई है। संक्रमण मुक्त हुए लोगों की संख्या लगातार 50वें दिन भी संक्रमण के नए मामलों से अधिक रही। अभी तक कुल 2,95,48,302 लोग संक्रमण मुक्त हो चुके हैं। कोविड-19 से मृत्यु दर 1.31 प्रतिशत है। देश में एक्टिव केसों की संख्या में लगातार गिरावट जारी है और यह आंकड़ा अब 509637 आ पहुंचा है। बीते 24 घंटे में कोरोना वायरस से 59,384 लोग रिकवर हुए हैं। इस तरह से अब तक कोरोना वायरस से 2,95,48,302 लोग ठीक हो चुके हैं। भारत में अब तक 34,00,76,232 टीकाकरण हो चुका है। कोरोना वायरस से ठीक होने वालों की संख्या पर गौर करें तो रिकवरी रेट बढ़कर 97.1 फीसदी हो गया है। वहीं, साप्ताहिक पॅजिटिविटी रेट 2.57 पर है।

महाराष्ट्र में सर्वाधिक मौतें- आंकड़ों के अनुसार देश में पिछले 24 घंटे में जिन 853 लोगों की मौत हुई, उनमें से महाराष्ट्र के 252 लोग, केरल के 124 लोग, तमिलनाडु के 102 लोग और कर्नाटक के 94 लोग थे। मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार, देश में अभी तक संक्रमण से कुल 4,00,312 लोगों की मौत हुई है, जिनमें महाराष्ट्र के 1,22,197 लोग, कर्नाटक के 35,134 लोग, तमिलनाडु के 32,721 लोग, दिल्ली के 24,981 लोग, उत्तर प्रदेश के 22,601 लोग, पश्चिम बंगाल के 17,735 लोग और पंजाब के 16,072 लोग थे।

ऐसे कहर बढ़ने के बाद ढलान पर आया कोरोना- देश में पिछले साल सात अगस्त को संक्रमितों की संख्या 20 लाख, 23 अगस्त को 30 लाख और पांच सितम्बर को 40 लाख से अधिक हो गई थी। वहीं, संक्रमण के कुल मामले 16 सितम्बर को 50 लाख, 28 सितम्बर को 60 लाख, 11 अक्टूबर को 70 लाख, 29 अक्टूबर को 80 लाख, 20 नवम्बर को 90 लाख के पार हो गए। देश में 19 दिसम्बर को ये मामले एक करोड़ के पार, चार मई को दो करोड़ के पार और 23 जून को तीन करोड़ के पार चले गए थे।